14.47 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 4th May, 1981, will consist of :—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from the Order Paper of today.

2. Consideration and passing of the following Bills as passed by Rajya Sabha:—

(i) The Essential Commodities (Special Provisions) Bill, 1981.

(ii) The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Suplies of Essential Commodities (Amendment) Bill, 1981.

(iii) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1981.

3. Consideration and passing of :—

The Marriage Laws (Amendment) Bill, 1981.

4. Discussion on the Motion given notice of by Shri R. K. Mhalgi for modification in the Notification regarding the Narmada Water Scheme.

5. Discussion on the Motion given notice of by Shri R. K. Mhalgi for modification in the Notification regarding Indian Telegraphs (4th Amendment) Rules, 1980.

सभापति महोदय : बागड़ी जी, आप को देख कर सब को बाई-पास कर देना पड़ता है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, किसान की हालत बिजाई से लेकर, जब तक फ़सल निकलती है, आशा पर जीवित रहती है परन्तु आज तक किसानों की आशा कभी सफल नहीं हुई सिवाय निराशा के । गेहूं के भाव के बारे में जो किसान की लुटाई हो रही है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी आधारित कीमत 130 रुपये क्विंटल है जबकि बाजार में 150 रुपये और दिल्ली में 170 रुपये और गुजरात में और बम्बई में 190 रुपये क्विंटल तक गेहूं की कीमत मिलती है । किसानों के साथ जो भाव की लूट हो रही है यानी किसान अपना गेहूं दिल्ली में नहीं बेच सकता है और सरकार हरियाणा में जबरन 130 रुपये क्विंटल खरीद रही है । जनता सरकार ने गुड़ पर रोक लगा कर गन्ने का भाव गिराया तो किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया जिसका नतीजा जहां चीनी फालतू पैदा होती थी, आज चीनी कहां । तीस साल की कड़ी मेहनत से किसानों ने इस देश को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और देश में अनाज इतना पैदा कर दिया कि विदेश से न मंगाना पड़े। अगर सरकार ने इस दफ़ा किसान को जो ओला और बवंडर से पिट चुका है, फसल की कीमत पूरी देने में असमर्थ रही या रुकावट डाली तो उसका नतीजा किसान गेहूं बोना बन्द कर देगा और देश भुखमरी का शिकार होगा । इसलिए अगले सप्ताह के लिये इस विषय को कार्यसूची में रखा जाए ।

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Junior Doctors of Delhi had been on strike for fifty eight days from 5th July, 1980 to 1st September, 1980. An agreement was arrived at between the Junior Doctors Federation of Delhi and the Government. Despite lapse of eight months it is yet to be implemented. Granting of advance increments after six years of residency service in the hospital regulation of long duty hours, rationalisation of pay scales, etc. agreed to in the agreement have yet to take con-

[Shri G. M. Banatwalla]

crete shape. Consequently, there is wide spread discontent among the Junior Doctors. The All India Medical Students Association have also decided to intensify the agitation unless agreement arrived at between the Government and the students of Delhi University College of Medicial Sciences in 1979 is implemented. It is necessary that the Government make a statement assuring expeditious implementation

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, बंगलोर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी यूनियनों के संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने कर्मचारियों की मांगों के बारे में भारत सरकार से समझौता वार्ता शुरु कराने की मांग को लेकर 29 अप्रैल से दिल्ली में संसद् भवन के सामने और बंगलोर हैदराबाद तथा देश के अन्य भागों में अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल आन्दोलन शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि गत 12 मार्च को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आश्वासन पर बंगलौर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले लगभग सवा लाख कर्मचारियों ने अपनी 77 दिनों की पुरानी हड़ताल वापस ले ली थी। लेकिन दुःख है कि, उसके बाद अभी तक सरकार ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से समझौता वार्ता शुरू नहीं की है।

सरकार की इस टालमटोल और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ कर्मचारियों में घोर असंतोष है जो किसी भी दिन बड़े आन्दोलन का रूप ले सकता है। अतः इस अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर इस सदन में बहस होनी चाहिए या श्रम मंत्री इसके संबंध में सदन के सम्मुख बयान प्रस्तुत कर कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने के लिए उचित कदम उठावें।

नम्बर दो, खबर है कि बिहार में 10 उर्दू अखबारों में काम करने वाले कई सौ श्रमजीवी पत्रकार, प्रेसकर्मचारी, कातिब आदि पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और अखबारों का प्रकाशन बंद है। उनकी एकमात्र मांग पालेकर अवार्ड की सिफारिशों को लागू करवाना है। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने बिहार के मुख्य मंत्री से वार्ता कर समझौता करवाने का प्रयास किया, पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है।

उर्दू के जिन अखबारों में हड़ताल है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) इन दिनों, (2) सदाये-आम, (3) संगम, (4) साथी, (5) देश-विदेश, (6) हमारा नारा, (7) कौमी तंजीम, (8) पैगामे नेहरू, (9) अजीमाबाद एक्सप्रेस और (10) सदाकत। इनमें 'संगम' और 'इन दिनों' को छोड़ कर दूसरे सभी अखबार सरकार के समर्थक हैं।

यह भी खबर है कि समाचार एजेंसी "हिन्दुस्तान समाचार" के श्रमजीवी पत्रकारों एवं कर्मचारियों" को मार्च महीने की तनख्वाह का अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे लोगों में घोर असंतोष है।

श्रम मंत्री को इन दोनों मामलों में हस्तक्षेप कर कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे पत्रकारों एवं कर्मचारियों का असंतोष दूर हो सके। इस संबंध में श्रम-मंत्री को कोई बयान देना चाहिए और साथ ही पालेकर अवार्ड के कार्यान्वियन पर बहस होनी चाहिए।

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise the following two points on the Government Business for the next week.

1. Asian Games. Over Rs. 700 crores are being wasted on this project. Our poor country cannot afford this huge expenditure. This money needs to be spent on development projects all over the country, particularly, projects related to power generation, irrigation, housing, flood prevention, cottage industries, etc. Cement, steel and other scarce commodities are being diverted to the Asian Games, and their prices are soaring in the black market. Today, there is a report in the Hindustan Times that important development projects, including work on the 500-bed Delhi Administration hospital at Hari Nagar in West Delhi have been held up because of concentration of all official efforts on the work related to Asian Games. The hospital earlier expected to cost Rs. 4 crores will now, whenever taken up, is expected to cost at least Rs. 2 crores more. This matter is far too serious and must be debated in the House, during the next week.

2. The hunger strike by the leaders and employees of the Bangalore-based public sector undertakings. This is a point which my hon. friend, Shri Ram Avtar Shastri, has also made. The strike by 1,30,000 employees of the five Bangalore-based public sector undertakings was called off after 77 days on assurances that the demands and grievances of the employees would be settled. Instead, the Government seem to be bent upon carrying on a war of attrition against the employees. Production in these five key public sector undertakings, ITI, HAL, HMT, BEL and BEML is vital for the nation's economy and security, and the present attitude of the Government is not helping matters. It is important that the matter is discussed in the House and Government take steps to settle the dispute and end the hunger-strike.

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor): Mr. Chairman, Sir, I wish to raise two points.

The first point is in regard to legislation for agricultural workers. There was a definite commitment on the part of the Government that a Bill for protecting the interests of agricultural workers will be brought forward in the current session. Particularly during the discussion of the demands for grants relating to the Labour Ministry, the hon. Labour Minister made such an announcement. I do not find any such item in the list of business for the next week. I would request the hon. Minister to kindly include the Bill in the next week's business.

My second point is in regard to the preparation and finalisation of the Sixth Plan. I am sorry to state that in the preparation and finalisation of such an important document as the Sixth Plan which is going to be the basis for the direction of development of our national economy for a period of five years, Parliament has been completely ignored.

MR. CHAIRMAN: You are not supposed to make a speech. You read out whatever you have given in writing.

SHRI P. K. KODIYAN: I would request the hon. Minister to provide some opportunity for discussing the Sixth Plan by Members of Parliament as it used to be done during the time of Jawaharlal Nehru's Prime Ministership.

15 hrs.

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : दो विषय मैं अगले सप्ताह की कर्य सूची में जुड़वाना चाहता हूं। पहला यह है कि देश के अधिकांश भागों में खास कर बिहार में बिजली का भयंकर संकट पैदा हो गया है। फलस्वरूप कृषि, उद्योग एवं विकास के कार्यों पर गहरा असर पड़ रहा है। बिजली संकट के कारण शहरों एवं देहातों में पेयजल के लिए अभी से हाहाकर मचा हुआ है। छोटे-मोटे कई उद्योग लगभग बन्द हो चुके हैं जिससे मजदूरों में बेरोजगारी

[श्रीविजय कुमार यादव]

बढ़ रही है । अतः इसे अगले सप्ताह की कार्य सूची में विचारार्थ रखा जाए ।

दूसरा यह है कि पूरे देश में शान्ति व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है और चोरी, डकैती, हत्या एवं बलात्कार के अलावा राजनैतिक हत्याओं की संख्या में भी उत्तरोत्तर तेजी से बढ़ौतरी हो रही है । हत्याओं में कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक दल के सदस्यों की भी हत्या की गई है । एक सौ ऐसे लोगों की अकेले बिहार राज्य में पिछले एक वर्ष में हत्या हुई है । उत्तरप्रदेश और बिहार में तथा दूसरे राज्यों में भी इस संख्या में बढ़ोतरी हो रही है । इसलिए इस विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में रखा जाना चाहिये ।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Since you have allowed me, I will speak. I am so fortunate.

MR. CHAIRMAN: When I am in the Chair, you are fortunate.

SHRI CHITTA BASU: Thank you, sir. I have sought your permission to raise two very important issues.

MR. CHAIRMAN: Please read what you have in writing.

SHRI CHITTA BASU: There are two important issues to be taken up for discussion next week. One is regarding the statement reported to have been made by the Chief Election Commissioner while announcing by-elections to serveral legislative assemblies of the States and to Lok Sabha, that a separate and independent election machinery will have to be set up in case of West Bengal. (*Interruptions*)

As per the functions and modus operandi of the Chief Election Commissioner and as per the provision of the Peoples Representation Act which is an Act of this Parliament, there is no provision for setting up an independent election machinery in any State.

While the existing State machineries provided by the State Governments are the exclusive . . . (*Interruptions*).

I am just making out a case

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): I do not know whether it is appropriate to discuss about the statement made by the Chief Election Commissioner of instituting an independent Election Commission in West Bengal or about the action of the Chief Election Commissioner.

SHRI CHITTA BASU: I am not discussing the action of the Chief Election Commissioner. To hold the elections is the duty of the Government. Since you have put the question, I have the opportunity of explaining.

(*Mr. Deputy Speaker in the Chair*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: MR. Chitta Basu, the subject which you have mention is "by-election in different States", and not the Chief Election Commissioner. So, please avoid. By-election is different.

SHRI CHITTA BASU: Just listen.

MR. DEPUTY-SPEAKER: elections should be held. They have not been held. Therefore, the matter is sub judice. Please don't go into the details.

SHRI CHITTA BASU: Do you want me to wait? I shall not take time. My point is . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: I had already made the observation on an adjournment motion yesterday.

SHRI CHITTA BASU: I am not saying that .....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please come to the subject. Look to the subject. Come to the subject now. You are a very Senior Member.

SHRI CHITTA BASU: That is the difficulty also in this subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a very reasonable Member.

SHRI CHITTA BASU: Then, listen to my reason.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Chitta Basu, by-elections should be held in different States. That is the subject. You insist on that.

Why do you go into details regarding why it was not held?

If the subject is allowed to be included in the Agenda, then you can discuss on that.

SHRI CHITTA BASU: By-elections are to be held in all States in accordance with the norms and practices and in accordance with the provisions of the Peoples Representation Act. But a statement has come out....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can not discuss about the statement. I will not allow it. You cannot discuss about the conduct of the Chief Election Commissioner. I will not allow it. This will not go on record.

SHRI CHITTA BASU: **

PROF. K. K. TEWARY (Buxar): On a point of order.

MR DEPUTY-SPEAKER: This has not gone on record.

SHRI CHITTA BASU: What I want to know from him is whether the by-elections in all parts of the coun- will be held in accordance with the practices, norms and the provisions of the law; this will also be in West Bengal; since some misunderstanding has been created by somebody—I do not mention....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The dates have already been announced.

SHRI CHITTA BASU: Therefore, Government should make a statement on this.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Madhukar.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में मैं दो बिन्दु रखना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before this item was put Mr. Chitta Basu, election dates have been announced.

श्री कमला मिश्र मधुकर : गेहूं की मंड़ियों में सरकार द्वारा गेहूं खरीदने की एजेन्सियों द्वारा छोटे किसानों द्वारा लाये गये गेहूं को खरीदने में उपेक्षा की जा रही है । इससे विचौलियों द्वारा उन्हें कम कीमतें मिल रही हैं और किसानों का शोषण हो रहा है । अस्तु, इस पर लोक सभा में अगले सप्ताह में चर्चा होनी चाहिये कि किसानों को गेहूं की उचित कीमत मिल सके ।

प्रधान मंत्री की आगामी यात्रा वाले विमान में सैबोटाज किया गया । इससे सारे देश में क्षोभ है । इस पर चर्चा होनी चाहिये कि ऐसी घटना क्यों हुई तथा इसमें कौन देश की एवं बाहरी शक्ति काम कर रही है तथा यह घटना सचमुच सत्य है या किसी वृहद षड़यंत्र का पूर्वाभास है ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री ने अगले सप्ताह की जो कार्य सूची पेश की है उसके मैं दो और विषयों पर चर्चा चाहता हूं ।

(1) जाति व धर्म संस्कृति तथा क्षेत्रीयता के आधार पर हमारे देश में कई संगठन कार्य कर रहे हैं। कुछ संगठन

*Not recorded.

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

हो सकता है अच्छा कार्य कर रहे हों। लेकिन कुछ संगठन बताते अपने आपको सांस्कृतिक हैं परन्तु उनके क्रियाकलाप सामाजिक व धार्मिक तनाव पैदा करने के कारण बने हैं। जमशेदपुर, अहमदाबाद अलीगढ़ या मुरादाबाद में घटित दुर्भाग्यजनक घटनाओं में इन संगठनों का हाथ होने का संदेह ही नहीं बल्कि तथ्यात्मक प्रमाण भी हैं। इसी प्रकार देश के कुछ भागों में जातीय व धार्मिक तनावों के पैदा करने में इन कुछ संगठनों का हाथ रह है और है। कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय तनावों को पैदा करने में क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का अपना स्वार्थ निहित है।

अतः देश में सामान्य विकास सहिष्णुता प्रेम व भाई चारे के वातावरण को पैदा करने व संवर्धन के लिये इस प्रकार की संस्थाओं, संगठनों व राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है। अतः सदन को इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है।

(2) हमारा राष्ट्र आज कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को नियंत्रित कर राष्ट्र के आर्थिक उत्थान के लिये आर्थिक उत्पादन के क्षेत्रों में अनुशासन का होना आवश्यक है।

वर्तमान कठिन समय में भी कुछ राजनैतिक दल किसानों को भड़का रहे हैं कि वे अपना उत्पादित माल बाजार में तब ही लावें जब उन्हें ऊंचे दाम प्राप्त हों। उपभोक्ता को भड़का रहे हैं कि कीमतें घटनी चाहिये। फैक्ट्री के मजदूरों को वेतनमानों के लिये हड़ताल करने के लिये उक्सा रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस आदि ऊंचे वेतनमानों वाले संगठन भी हड़ताल कर रहे हैं।

आज राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि उत्पादन बढ़े तब ही कीमतें घट सकती हैं, उपलब्धता बढ़ सकती है तथा उन्हें ऊंचे वेतनमान प्राप्त हो सकते हैं। मैं हड़ताल करने के अधिकार का समर्थक हूं परन्तु समय की आश्यकता है कम से कम तीन वर्ष के लिये किसी भी प्रकार की हड़तालों व अवरोध किये जाने पर प्रतिबन्ध लगना आवश्यक है। अतः माननीय सदन इस पर विचार करे।

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram): Seven Trade Union of Neyveli Lignite Corporation Ltd. a Government of India enterprise under the Ministry of Coal and Energy, Neyveli have jointly served a strike notice to the management demanding higher fixation of incentives and coverage of incentive schemes to all the sections of the employees of NLC Ltd., on the grounds of the appreciable overall production in the industry.

Now the Tamil Nadu Government is facing acute power crisis. The NLC Ltd. could at least meet the basic needs of the power requirements.

It is our anxiety and great concern that Tamil Nadu should not be left in dark and gloom in the event of precipitated power failure due to the anticipated strike in NLC Ltd., Neyveli. I pray that that should not happen.

In view of the serious outcome of an anticipated strike and much hardship to the Tamil Nadu in general and the families of the employees of NLC Ltd., Neyvli in particular, the strike can be averted if the concerned authorities could intervene for an amicable settlement immediately.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You want this item to be included.

DR. V. KULANDAIVELU: I want that this item be included in the next week's list of business so that a discussion could take place on the

subject of urgent public importance.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): I wish to raise the folloing points.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The difficulty is that no hon. Member sees the clock. We have only to see the clock. At 3.30 we will have the Private Members' Business. So, Mr. Mandal, make your points. Don't make a speech.

SHRI MUKUNDA MANDAL: Regarding the Metro Railway in Calcutta, the Minister of Railways assured the House that the first phase of the project would be completed in the year 1984-85 and the second phase of the project would be completed by 1986-87. But during the recent visit of the Deputy Railway Minister to Calcutta he made a statement that there is a doubt about the completion of the first phase as well as the second phase of the Metro Railway. I urge upon the Government and urge upon the Minister to clarify the position because confusion has taken place and people are doubtful. That is why I request the Minister through you to include this one in the next weeks business.

The second one I want to raise is the cement crisis in West Bengal. Due to the cement crisis in West Bengal all construction work and all development work has already been stopped and the Sealdah fly-over which is the most important project taken up by the West Bengal Government is facing a tremendous difficulty due to the scarcity of cement and that cement crisis is there throughout West Bengal. My point is that the quota of cement for West Bengal has been decreased and the decreased quota also is not yet supplied by the Government...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You put the question to the Government why it was decreased and how it was decreased. You consult your Professor-friend.

SHRI MUKUNDA MANDAL: This should also be included in the next week's business.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Some of the hon. Members have made some suggestions and suggested that their suggestions should be taken up in the next week's business. In the Business Advisory Committee, the consensus was that it may be left to the Speaker to select the subjects that are necessary to be discussed. So now it has been left to the discretion of the Speaker. What we can do is that we will communicate all these suggestions to the Speaker to take whatever action he deems fit in the circumstances.

OIL AND NATURAL GAS COMMISSION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we go to the next item. Clause by clause consideration to be taken up.

Clause 2—(*Amendment of section 5*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Giri, are you moving?... You are not in a mood to move, I think... Let us complete this Bill and then go to the Private Members' Business.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): I am moving, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are moving all the amendments?

SHRI SUDHIR GIRI: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, very good.

SHRI SUDHIR GIRI: I want to speak, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no time... All right. Why should I stand in the way, if you are able to convince the Minister to accept your amendment? You can make it short.

SHRI SUDHIR GIRI: I beg to move: